NFHS-5 डेटा साक्षरता और सेवाओं के वितरण को दर्शाता है, धर्म को नहीं

लेखक- एस. वाई. कुरैशी (भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (स्वास्थ्य) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

11 मई, 2022

भारत ने अपनी जनसंख्या के लिए प्रतिस्थापन दर हासिल कर ली है। अब, परिवार नियोजन उपकरणों के लिए "अधूरी जरूरतों" (unmet needs) को पूरा करना चाहिए।

प्रतीक्षा समाप्त हुई। लगभग छह महीने से प्रतीक्षित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) की रिपोर्ट आखिरकार आ गई है और यह एक सुखद दृष्टिकोण प्रदान करता है।

एनएफएचएस एक बड़ा बहुस्तरीय सर्वेक्षण है, जो अन्य बातों के साथ-साथ प्रजनन क्षमता, शिशु और बाल मृत्यु दर, परिवार नियोजन, प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण, एनीमिया, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन सेवाओं की गुणवत्ता और उपयोग के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसकी शुरुआत 1992-93 में हुई थी और इसका पाँचवाँ दौर 2019-21 में हुआ है।

सर्वेक्षण नीति और कार्यक्रम के उद्देश्यों के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और अन्य एजेंसियों द्वारा आवश्यक डेटा प्रदान करते हैं। मंत्रालय ने इस कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (IIPS), मुंबई को नोडल जिम्मेदारी सौंपी है। आईआईपीएस विभिन्न राज्यों में सर्वेक्षण करने के लिए कई क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग करता है। कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने में शामिल हैं, मुख्य रूप से यूएसएआईडी, डीएफआईडी, यूनिसेफ और यूएनएफपीए।

रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत ने अंततः 2.1 TFR (कुल प्रजनन दर एक महिला के अपने जीवनकाल में कुल बच्चों की संख्या है) की प्रतिस्थापन दर हासिल कर ली है। वास्तव में, यह 2.0 के निशान से नीचे चला गया है। बेशक, बड़े अंतर्राज्यीय बदलाव हैं। कई राज्य प्रतिस्थापन स्तर से काफी नीचे हैं, जो उन पाँच राज्यों के लिए क्षतिपूर्ति कर रहे हैं जो राष्ट्रीय औसत 2 से ऊपर हैं।

पिछड़ने वाले राज्य यूपी, बिहार, झारखंड, मणिपुर और मेघालय हैं। गौरतलब है कि मूल रूप से हिंदी भाषी चार राज्य थे जिनका आँकड़ा खराब रहा है अर्थात् बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश और इन राज्यों को एक विशेष नाम दिया गया है- बीमारू राज्य (BIMARU)। इस समूह से बाहर निकलने के लिए दो राज्यों, राजस्थान और मध्य प्रदेश ने संघर्ष किया है जबकि झारखंड और दो पूर्वोत्तर राज्यों ने उनकी जगह ले ली है। यूपी और बिहार अपने विशाल आकार के कारण राष्ट्रीय औसत को नीचे खींच रहे हैं। उनका टीएफआर राष्ट्रीय औसत 2 से नीचे है, जिसमें बिहार में 3, मेघालय में 2.9, यूपी में 2.4, झारखंड में 2.3 और मणिपुर में 2.2 है।

राजस्थान और मध्य प्रदेश 2 के टीएफआर पर पहुँच गए हैं, जो उनके प्रयासों की सफलता को दर्शाता है। हालाँकि यह देखकर खुशी होती है कि अधिकांश राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश प्रतिस्थापन दर से काफी नीचे चले गए हैं, इन राज्यों में कुछ दशकों में उनकी आबादी में गिरावट शुरू हो जाएगी।

आँकड़े और भी बेहतर होते यदि परिवार नियोजन के लाभों से अवगत कराए गए सभी लोगों को उनकी वांछित सेवाएँ प्राप्त होतीं। यहाँ, "अधूरी जरूरतों" (unmet needs) की अवधारणा को समझना महत्त्वपूर्ण है। लोगों को परिवार नियोजन की आवश्यकता और विधियों से अवगत कराना और उन्हें परिवार नियोजन अपनाने के लिए प्रेरित करना काफी कठिन है। सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि कठिन कार्य को प्राप्त करने के बाद, हम समुदायों की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं जो अभी भी 9.4 प्रतिशत पर बहुत अधिक है। मुसलमानों की "अधूरी जरूरतें" सबसे अधिक बनी हुई हैं, जो 11.8 प्रतिशत है और यह पाँच साल पहले 16.4 प्रतिशत थी, जो कि एक अच्छा संकेत है। मुसलमानों की तुलना में, हिंदुओं की अधूरी जरूरत 9 फीसदी है। यदि हम इस मुद्दे पर एक मिशन मोड में ध्यान केंद्रित करते हैं, तो परिवार नियोजन के प्रदर्शन में नाटकीय रूप से सुधार होगा।

सर्वेक्षण द्वारा उजागर किया गया एक अन्य मुद्दा परिवार नियोजन के प्रति पुरुषों का रवैया है। वे महिलाओं पर जन्म नियंत्रण का भार डालते हैं। 35 फीसदी पुरुषों का मानना है कि गर्भ निरोधकों का इस्तेमाल करना एक महिला की जिम्मेदारी है। वे इस तथ्य की अनदेखी करते हैं कि पुरुष नसबंदी महिला ट्यूबेक्टोमी की तुलना में बहुत सरल प्रक्रिया है। बात यहाँ नसबंदी की नहीं है, यहाँ तक कि सबसे सरल गर्भनिरोधक यानी कंडोम का भी उपयोग बेहद कम है। यह सामाजिक विपणन के माध्यम से एक अधिक प्रभावी व्यवहार परिवर्तन संचार कार्यक्रम की माँग करता है।

एक और अच्छी खबर यह है कि परिवार नियोजन की मुस्लिम स्वीकृति की गति अन्य सभी समुदायों की तुलना में तेजी से तीन दशकों में फैले पाँच सर्वेक्षणों के माध्यम से जारी रही है। हालाँकि मुस्लिमों में जन्म नियंत्रण प्रथा अभी भी सबसे कम है- 47.4 प्रतिशत (एनएफएचएस-4 में 45 प्रतिशत से ऊपर)।

लेकिन जिस बात की अनदेखी की जाती है, वह यह है कि अन्य समुदाय- उदाहरण के लिए, हिंदू 58 प्रतिशत (56 प्रतिशत से ऊपर) के साथ पीछे नहीं हैं। इस परिदृश्य को बदलना होगा क्योंकि जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव की कल्पना की जा सकती है जब 80 प्रतिशत आबादी में से 42 प्रतिशत परिवार नियोजन का अभ्यास नहीं कर रहे हैं।

प्रजनन को प्रभावित करने वाले कारकों को समझना महत्त्वपूर्ण है। यह आमतौर पर प्रतिपादित धर्म नहीं है, बल्कि साक्षरता, विशेष रूप से लड़कियों की आय, परिवार नियोजन का वितरण और स्वास्थ्य सेवाएँ हैं जो महिलाएँ स्कूल नहीं जाती हैं, उनका टीएफआर 2.8 है, जबकि बारहवीं कक्षा पूरी करने वालों के लिए यह आँकड़ा 1.8 है। आँकड़ा एक का समान अंतर गरीबी के संदर्भ में देखा जा सकता है, जहाँ सबसे गरीब वर्ग में सबसे अमीर की तुलना में अधिक टीएफआर है।

चूँकि मुस्लिम तीनों सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सबसे पिछड़े हैं, इसलिए परिवार नियोजन में उनका पिछड़ापन समझ में आता है लेकिन यह स्वीकार्य नहीं है। दुर्भाग्य से, इन मुद्दों को हल करने के लिए बहुत अधिक प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो की भरमार है जहाँ हिंदू मण्डली को मुसलमानों के साथ कोई व्यापार नहीं करने और उनके सामाजिक एवं आर्थिक बहिष्कार से उन्हें आर्थिक रूप से पंगु बनाने की शपथ दिलाई जा रही है। इसका असर कई स्कूलों में मुस्लिम बच्चों को प्रवेश से वंचित करने में दिखाई दे रहा है।

राजनीति को पीछे छोड़ने और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करने का समय आ गया है। भ्रामक आख्यानों के बजाय, हमें प्रजनन व्यवहार के वास्तविक निर्धारकों- साक्षरता, आय सृजन, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन सेवाओं में सुधार को संबोधित करने की आवश्यकता है। इससे देश अपेक्षा से बहुत जल्दी जनसंख्या स्थिरीकरण की ओर अग्रसर हो जाएगा।

जीएस वर्ल्ड टीम इनपुट

IN THE NEWS

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5)

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 को जारी किया गया है।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (National Family Health Survey- NFHS) बड़े पैमाने पर किया जाने वाला एक बहुस्तरीय सर्वेक्षण है जो पूरे भारत में परिवारों के प्रतिनिधि नमूने के आधार पर किया जाता है।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) की रिपोर्ट के अनुसार करीब 35.1 प्रतिशत पुरुषों का मानना है कि गर्भनिरोधक अपनाना "महिलाओं का काम" है जबकि 19.6 प्रतिशत पुरुषों का मानना है कि गर्भनिरोधक का उपयोग करने वाली महिलाएँ 'स्वच्छंद' हो सकती हैं।
- एनएफएचएस-5 सर्वेक्षण में देश के 28 राज्यों और आठ केंद्रशासित प्रदेशों के 707 जिलों से करीब 6.37 लाख नमूने घरों में आयोजित किए गए सर्वेक्षण में 7,24,115 महिलाओं और 1,01,839 पुरुषों को शामिल किया गया।
- इस राष्ट्रीय रिपोर्ट में सामाजिक-आर्थिक सहित विभिन्न आधार पर आँकड़े मुहैया कराए गए हैं जिससे नीति निर्माण और प्रभावी कार्यक्रम कार्यान्वयन में मदद मिल सकती है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि चंडीगढ़ में सबसे अधिक 69 प्रतिशत पुरुषों का मानना है कि गर्भनिरोधक अपनाना महिलाओं का काम है और पुरुषों को इसके संबंध में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं केरल में सर्वेक्षण में शामिल 44.1 प्रतिशत पुरुषों के अनुसार गर्भनिरोधक का उपयोग करने वाली महिलाएँ 'स्वच्छंद' हो सकती हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार 55.2 प्रतिशत पुरुषों का कहना है कि अगर पुरुष द्वारा कंडोम का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह ज्यादातर मामलों में गर्भधारण नहीं होने देता है।
- सर्वेक्षण में शामिल पुरुषों में, करीब 64.7 प्रतिशत सिखों का मानना था कि गर्भनिरोधक महिलाओं का काम है और पुरुषों को इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, जबकि सर्वेक्षण में शामिल हिंदुओं में यह संख्या 35.9 प्रतिशत और मुसलमानों के लिए 31.9 प्रतिशत थी।
- इसमें कहा गया है कि आय के साथ ही आधुनिक गर्भनिरोधकों का उपयोग भी बढ़ता है और कम आय वाले समूह में 50.7 प्रतिशत महिलाएँ इसका उपयोग करती हैं वहीं उच्चतम आय वाले समूह में यह 58.7 प्रतिशत है।
- आँकड़ों के अनुसार कामकाजी महिलाओं में आधुनिक गर्भनिरोधक का उपयोग करने की अधिक संभावना है क्योंकि ऐसी 66.3 प्रतिशत महिलाएँ आधुनिक गर्भनिरोधक पद्धति का उपयोग करती हैं जबकि गैर-कामकाजी समूह में यह प्रतिशत 53.4 प्रतिशत है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के बारे में

- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) संपूर्ण भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के सन्दर्भ में भारतीय परिवारों के एकत्र किए गए विभिन्न नमूनों का एक सर्वेक्षण है।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा इस सर्वेक्षण के लिए IIPS को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है, जो NFHS के लिए समन्वय और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।
- पहला राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-1) 1992-93 में आयोजित किया गया था।
- एनएफएचएस को कई चरणों में जारी करने का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा अन्य उभरते मुद्दों से संबंधित विश्वसनीय और तुलनात्मक आँकड़े प्राप्त करना होता है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (National Family Health Survey-NFHS) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

1. पहला राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-1) 1992-93 में आयोजित किया गया था।
2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा इस सर्वेक्षण को जारी किया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(क) केवल 1 **(ख)** केवल 2

(ग) 1 और 2 दोनों **(घ)** न तो 1, न ही 2

Expected Question (Prelims Exams)

Q. Consider the following statements in the context of National Family Health Survey (NFHS):-

1. The first National Family Health Survey (NFHS-1) was conducted in 1992-93.
2. This survey is released by the Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW).

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1 **(b)** Only 2

(c) Both 1 and 2 **(d)** Neither 1, nor 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. 'राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण' से आप क्या समझते हैं? भारत में महिलाओं की स्वास्थ्य की स्थिति पर एनएफएचएस-5 द्वारा उजागर की गई चिंताओं के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

Q. What do you understand by 'National Family Health Survey'? Discuss about the concerns highlighted by NFHS 5 on the health status of women in India. (250 Words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।